



**International Journal of Advanced Research in
Education and TechnologY (IJARETY)**

Volume 11, Issue 2, March 2024

Impact Factor: 7.394



राजस्थान के प्रजामण्डल आन्दोलन में आदिवासी समुदाय की भूमिका का विश्लेषण

विरेन्द्र सिंह यादव

सहायक आचार्य, इतिहास, चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय, श्री गंगानगर, राजस्थान
सार

प्रजामण्डल का अर्थ है प्रजा का संगठन। सन 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ गए। इस कारण किसानों द्वारा विभिन्न आंदोलन चलाये जा रहे थे, साथ ही देश भर में गांधी जी के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आन्दोलन भी चल रहा था। इन सभी के कारण राज्य की प्रजा में जागृती आयी और उन्होंने संगठन(मंडल) बना कर अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया जो प्रजामण्डल आंदोलन कहलाये।

परिचय

जयपुर प्रजामण्डल(1931)

सन 1931 में कर्पूरचन्द पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामण्डल की स्थापना की गयी।

सन 1936 में जयपुर प्रजामण्डल का पुनर्गठन हुआ एवं चिरंजीलाल मिश्र अध्यक्ष को बनाया गया।

सन 1938 में जयपुर प्रजामण्डल अध्यक्ष जमना लाल बजाज को बनाया गया।

सन 1942 में जयपुर प्रजामण्डल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेन्टलमेन्स समझौता हुआ। जिसमें प्रजामण्डल को भारत छोड़ो आन्दोलन से अलग रखा गया।

इसके बाद प्रजामण्डल से अलग होकर एक नए संगठन का निर्माण किया गया जिसका नाम आज़ाद मोर्चा रखा गया, जिसने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारम्भ किया।

जयपुर प्रजामण्डल राजस्थान का प्रथम प्रजामण्डल था।[1,2,3]

मेवाड़ प्रजामण्डल(24 अप्रैल 1938)

मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा को जाता है। उनके प्रयासों से उदयपुर में 24 अप्रैल 1938 को बलवंतसिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना की गयी।

25-26 नवम्बर 1941 में मेवाड़ प्रजामण्डल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में हुआ, जिसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया।

प्रजामंडल ने बेगार एवं बलेठ प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया।

9 अगस्त 1942 को शुरू किये गए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।[1,2,3]

मारवाड़ प्रजामण्डल(1934)

सन 1934 मारवाड़ प्रजामण्डल की स्थापना जयनारायण व्यास(शेर-ए-राजस्थान) ने जोधपुर में की एवं भंवरलाल सर्राफ को मारवाड़ प्रजामण्डल का अध्यक्ष बनाया गया।

सन 1937 में मारवाड़ प्रजामण्डल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया।

इसके बाद 1938 में रणछोड़ दास गट्टानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद् का गठन हुआ।

मारवाड़ लोक परिषद् में महिमा देवी किंकर के नेतृत्व में महिलाओं ने भाग लिया।
1942 में मारवाड़ लोक परिषद् ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया।
3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास के नेतृत्व में एक मिलीजुली लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया।
३० मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया।

भरतपुर प्रजामण्डल(1938)

भरतपुर रियासत में अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति की विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गयी।
इसके बाद 1938 में श्री किशन लाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामण्डल की स्थापना की गयी।
1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामण्डल के अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती बोहरा कर रही थी।

बूंदी प्रजामण्डल(1931)

सन् 1931 में श्री कांतिलाल द्वारा स्थापित किया गया ।
बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना १९ जुलाई 1944 में हरिमोहन माथुर एवं बृजसुंदर शर्मा द्वारा की गई।

कोटा प्रजामण्डल(1934)

हाड़ोती प्रजामण्डल के नाम से नयनूराम शर्मा एवं प्रभुलाल विजय द्वारा की गयी।
इसके बाद सन् 1938 में नयनूराम शर्मा व अभिन्न हरि द्वारा कोटा प्रजामण्डल गठित किया गया।

करौली प्रजामण्डल(18 अप्रैल 1939)

18 अप्रैल, 1939 में श्री त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह द्वारा गठित।

धौलपुर प्रजामण्डल(1936)

सन् 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल, श्री मूलचंद श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आदि द्वारा गठित।

बीकानेर प्रजामण्डल(4 अक्टूबर 1936)

4 अक्टूबर, 1936 को वैद्य मघाराम(अध्यक्ष) व श्री लक्ष्मणदास स्वामी द्वारा गठित किया गया।
राजस्थान का एकमात्र प्रजामण्डल जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई।
22 जुलाई 1942 में रघुवरदयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद् का गठन किया गया।

शाहपुरा(18 अप्रैल 1938)[4,5,6]

18 अप्रैल, 1938 को श्री रमेशचन्द्र औझा, लादूराम व्यास व अभयसिंह डांगी द्वारा श्री माणिक्य लाल वर्मा के सहयोग से गठित किया गया।
शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की।

अलवर प्रजामण्डल(1938)

सन् 1938 में पं. हरिनारायण शर्मा एवं कुंजबिहारी मोदी द्वारा स्थापित किया गया। सन् 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सरदार नथामल इसके अध्यक्ष बने।

सिरोही प्रजामण्डल(23 जनवरी 1939)

23 जनवरी, 1939 को श्री गोकुलभाई भट्ट(राजस्थान का गाँधी) की अध्यक्षता में सिरोही प्रजामण्डल का गठन हुआ।

किशनगढ़ प्रजामण्डल(1939)

1939 में श्री कांतिलाल चौथानी एवं श्री जमालशाह(अध्यक्ष) द्वारा स्थापित हुआ।

कुशलगढ़ प्रजामण्डल(अप्रैल 1942)

अप्रैल, 1942 में श्री भंवरलाल निगम(अध्यक्ष) व कन्हैयालाल सेठिया द्वारा गठित हुआ।

बांसवाड़ा प्रजामण्डल(1943)

सन् 1943 में भूपेन्द्रनाथ त्रिवेदी, धूलजी भाई भावसर, मणिशंकर नागर आदि द्वारा स्थापित।

डूंगरपुर प्रजामण्डल(1 अगस्त 1944)[4,5,6]

भोगीलाल पाड्या (वागड़ का गांधी) एवं शिवलाल कोटरिया द्वारा गठित किया गया।

प्रतापगढ़ प्रजामण्डल(1945)

सन् 1945 में श्री चुन्नीलाल एवं अमृतलाल के प्रयासों से स्थापित हुआ।

जैसलमेर प्रजामण्डल(15 दिसम्बर 1945)

15 दिसम्बर, 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामण्डल की स्थापना की।

झालावाड़ प्रजामण्डल(25 नवम्बर 1946)

25 नवम्बर, 1946 को श्री मांगीलाल भव्य(अध्यक्ष), कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम द्वारा गठित गया।

विचार-विमर्श

उदयलाल वरदिया का जन्म सन् 1918 को हुआ। जब आपकी उम्र 20 वर्ष की थी तभी आपके पिता राम वरदिया व माताजी श्रीमती चुन्नीबाई दोनों का निधन हो गया। वरदिया ने 1934 से सलूमबर में ठिकाने के अधिकारियों द्वारा गरीब किसानों पर जो अन्याय होते थे उनके विरुद्ध व्यक्तिगत स्तर पर रियासत में शिकायत करवाना शुरू किया। लोगों को उससे राहत मिलने पर काफी लोग आपके पास आने लगे। 1938 में जब उदयपुर में मेवाड़ प्रजामण्डल की शुरूआत हुई, तब सलूमबर में भी माणिक्यलाल वर्मा की प्रेरणा से ही तहसील प्रजामण्डल दफ्तर का उद्घाटन हुक्मीचन्द सुराणा के हाथों करवाया गया। पन्नालाल जी वकील उसके अध्यक्ष बनाए गए व आप मन्त्री बने। उसी दिन से सलूमबर में खादी पहनने का प्रचलन बढ़ गया। वरदिया ने 1940 ई. में आदिवासियों का एक संगठन बनाया। संगठन के माध्यम से आपने आंदोलन चलाकर जागीरदार जो प्रति परिवार धान (अनाज) सिर पर लदवा कर उदयपुर मंगवाते थे, उसको बंद

करवाया। उक्त सफलता से आदिवासियों का संगठन और अधिक मजबूत बन गया। उसका कार्यक्षेत्र सराहा तक बढ़ गया। आपके नेतृत्व में संगठन में सामाजिक सुधार के कई कार्य किए। [7,8,9] जिसमें शराब छुड़ाना, मुर्दा पशु का मांस छुड़ाना, पाठशालाएं खुलवाकर बच्चों में अध्ययन की रूचि पैदा करना शामिल थे। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आन्दोलन में उदयलाल वरदिया ने सक्रिय भाग लिया तथा गिरफ्तार हो कर 9 माह जेल में रहे। जेल से मुक्त होने के बाद वरदिया ने महाराणा के पालतू लाखों सूअरों द्वारा किसानों को फसल उजाड़ने को बन्द करवाने के लिए सराड़ा, सलूमबर तहसील के किसानों का एक संगठन बनाकर सूअरों को मारे जाने के आन्दोलन को निरन्तर एक वर्ष चला कर मेवाड़ सरकार से मांग पूरी करवा कर, किसानों को राहत पहुंचाई। [7,8,9]

राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भील निवास करते हैं, जो मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वे कुशलगढ़ के इलाके हैं। भील अत्यन्त परम्परावादी जाति है जो अपने सामाजिक व आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परम्परागत अधिकारों का हनन हुआ तो इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया, चाहे वह फिर अंग्रेजों के विरुद्ध हो या फिर शासक के विरुद्ध हो। 1. गोविन्द गुरु व भगत आन्दोलन: गोविन्द गुरु एक महान् समाज सुधारक थे जिन्होंने भी के सामाजिक व नैतिक उत्थान का बीड़ा उठाया। उन्हें सामाजिक दृष्टि से संगठित करके मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। 2. सम्प – सभा की स्थापना: गोविन्द गुरु ने भीलों की सेवार्थ 1883 ई. में 'सम्प-सभा' की स्थापना की। राजस्थान की भाषा में 'सम्प' का अर्थ 'प्रेम' होता है। इस सभा के माध्यम से वह मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन संशकित हो उठ और भीलों को 'भगत पन्थ' छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब उन्हें बेगार व कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगल में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया, तो वे आन्दोलन के लिए विवश हो गए। गोविन्द गुरु के प्रयासों से शिक्षा का प्रचार होने के साथ-साथ सुधार भी होने लगी। उदाहरण के लिए जब भील में मद्यपान का प्रचलन कम होने लगा, तो कुशलगढ़ व बांसवाड़ा राज्य को आबकारी क्षेत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा। [10,11,12] अंग्रेजों ने इस सुधार व संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की सम्भावना व्यक्त की। 3. आन्दोलन की प्रगति व दमन – चक्र : अप्रैल, 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा पहले गिरफ्तार और फिर रिहा किए जाने के बाद गोविन्द गुरु अपने साथियों के साथ ईडर राज्य में मानगढ़ की पहाड़ी पर चले गए जो बांसवाड़ा वसथ राज्य की सीमा पर स्थित है। अक्टूबर, 1913 को उन्होंने अपने सन्देश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्र होने के लिए कहा। भील भारी संख्या में हथियार लेकर एकत्र हो गए। उनके द्वारा बांसवाड़ा राज्य के दो सिपाहियों को प्रीय गया। सूथ, किले पर हमला किया गया। इस कार्यवाही ने सूथ, बांसवाड़ा, ईडर व डूंगरपुर राज्यों को चौकन्ना कर दिया। ए. जी. जी. की स्वीकृति मिलते ही इसे 6 से 10 नवम्बर, 1913 के बीच मेवाड़ भील की दो कम्पनियों, 104 वेलेजली राइफल्स की एक कम्पनी, राजपूत रेजीमेण्ट की एक कम्पनी व जाट रेजीमेण्ट की एक कम्पनी मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुँच गई और गोलाबारी करके भीलों को मार दिया। सरकारी आँकड़ों के अनुसार इस कार्यवाही में पन्द्रह सौ भील मारे गए। इस नरसंहार को कई इतिहासकारों ने जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड से भी अधिक वीभत्सकारी बताया है। इस प्रकार भगत आन्दोलन निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। गोविन्द गुरु को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। यह तो स्पष्ट है कि भीलों की कोई महती राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी, किन्तु उनमें व्याप्त सामाजिक एकता भी अंग्रेजों व शासकों के लिए चुनौती बन गई। गोविन्द गुरु अहिंसा के पक्षधर थे व उनकी श्वेत ध्वजा शान्ति का प्रतीक थी। इस आन्दोलन के परिणाम दूरगामी सिद्ध हुए। भीलों के साथ-साथ समाज के दूसरे वर्गों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई। मोतीलाल तेजावत व एकी आन्दोलन अंग्रेजों द्वारा भगत आन्दोलन कुचल दिए जाने के बाद भीलों का आन्दोलन कुछ समय के लिए निष्क्रिय हो गया। फिर भी भगत आन्दोलन का प्रभाव भीलों की राजनीतिक चेतना पर पड़ा। भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 में भी व गरसियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति व बेगार के प्रति अपना विरोध जताया। कोई परिणाम न निकलता देखकर 1921 में बिजौलिया किसान आन्दोलन से प्रभावित होकर पुनः महाराणा को अत्यधिक लागतों व कामगारों के शोषणात्मक व्यवहार के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। इन सभी अहिंसात्मक प्रयासों का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो भोमट के खालसा क्षेत्रों के भीलों ने लागते व बेगार चुकाने से इन्कार कर दिया 1921 में भीलों को मोतीलाल तेजावत का नेतृत्व प्राप्त हुआ। तेजावत ने भीलों को लगान व बेगार न देने के लिए प्रेरित किया। एक्की आन्दोलन के नाम से विख्यात इस आन्दोलन को जनजातियों के राजनीतिक जागरण का प्रतीक माना जा सकता है। डूंगरपुर के महारावल ने आन्दोलन फैल जाने के भय से सभी प्रकार की बेगारें अपने राज्य से समाप्त कर दीं। जागीरी क्षेत्रों में भीलों को यह सुविधा न मिल पाने के कारण एक्की आन्दोलन' संगठित रूप से तेजावत के नेतृत्व में भोमद क्षेत्र के अतिरिक्त सिरोही व गुजरात क्षेत्र में भी फैलने लगा। अंग्रेजी सरकार ने अब दमनात्मक नीति अपनाई। 7 अप्रैल, 1922 को ईडर क्षेत्र में माल नामक स्थान पर मेजर सदन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने गोलीबारी की। 3 जून, 1929 को ईडर राज्य ने तेजावत को गिरफ्तार कर मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। मेवाड़ के सर्वोच्च न्यायालय महोदयराज सभा ने लिखित में तेजावत से राज्य के विरुद्ध कार्य न करने का आश्वासन माँगा। गाँधीजी के निकट सहयोगी मणिलाल कोठवरी के हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ। 16 अप्रैल, 1936 को तेजावत ने लिखित में इच्छित आश्वासन दिया और 23 अप्रैल को वह रिहल कर दिए गए। [7,8,9]

परिणाम

आजादी से पहले जब राजस्थान के आदिवासी इलाकों में साजिश के तहत शिक्षा के उजियारे को जुलमत के अंधेरे से मिटाया जा रहा था। पाठशालाओं में तालाबन्दी कर गुरुजनों को घसीट कर मारा-पीटा जा रहा था। सरकारी दहशतगर्दी के उस माहौल में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छोटे से गांव रास्तापाल की काली बाई भील अपने गुरु को बचाने के लिए हाथ में हंसिया लेकर हुकूमत के सैनिकों से अकेले भिड़ गई थी।

रास्तापाल गांव की पाठशाला के गुरु सेंगाभाई की जान बचाते हुए काली बाई भील उस समय के जुल्मी शासन की बंदूक की गोलियों की शिकार हुई। 20 जून 1947 को उसने प्राण त्याग दिए। बीते मंगलवार को काली बाई भील का बलिदान दिवस था, लेकिन न तो सरकारी स्कूलों में काली बाई भील के बलिदान को याद किया गया न ही आदिवासियों की बेहतरी का दम भरने वाले संगठनों में चर्चा हुई।

राजस्थान में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काली बाई भील स्कूटी सरकारी योजना को छोड़ दें तो किताबों में कहीं भी काली बाई भील के बलिदान को नहीं पढ़ाया जाता। यह विचारणीय है। आदिवासी काली बाई भील के बलिदान के इतिहास को आखिर क्यों बिसरा दिया गया? इसको लेकर द मूकनायक ने पूर्व सहायक प्रोफेसर दिल्ली विश्वविद्यालय एवं स्वतंत्र लेखन एवं आदिवासी रचनाकार डॉ. हीरा मीणा से बात की। मीणा ने कहा कि वह इस संबंध में कई बार लिख चुकी हैं। यही सवाल उन्हें भी कचोटता है। आखिर काली बाई भील के बलिदान को इतिहासकारों ने क्यों छिपाया है।

मीणा कहती हैं कि जान की बाजी लगाकर 13 साल की मासूम ने हाथ में रखी हंसिया से पाठशाला के अध्यक्ष सेंगाभाई की जान बचाकर अंग्रेजों की एक टुकड़ी को भगाया था। देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले अदिवादियों को इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया है! उन्होंने कहा कालीबाई भील के बलिदान का इतिहास हमें पढ़ाया गया होता तो क्या आज हमारी बच्चियों को देश प्रेम और की प्रेरणा नहीं मिलती [13]

मीणा ने कहा आजादी से दो महीने पहले ब्रिटिश हुकूमत और डूंगरपुर महारावल लक्ष्मणसिंह की साजिशों और आदेशों के कारण आदिवासी अंचल के शिक्षा के प्रकाश स्तम्भ पाठशालाओं को जबरन बंद करवाया जा रहा था। वे नहीं चाहते थे कि आदिवासियों के बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा मिले। उन्हें डर था कि आदिवासी बच्चे शिक्षा प्राप्त करके अपने हक अधिकारों की बात करेंगे। उनके गुलाम-बेगारी बनकर नहीं रहेंगे।

वे उन्हें उनके पुरखों के गौरवशाली इतिहास से भी अनभिज्ञ रखना चाहते थे। जबकि सच्चाई यह है कि डूंगरपुर को 13वीं शताब्दी में वीर योद्धा डूंगरीया भील के द्वारा बसाया गया था। संसार की सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, ढुंढाड़ क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों में सिंधुघाटी सभ्यता के वंशज भील, मीणाओं का साम्राज्य स्थापित था, जिसको राजपूतों ने छल-कपट और कुटनीति से हथियाया था।

वीर बाला कालीबाई भील कलसुआ डूंगरपुर जिले के रास्तापाल गांव की एक भील बालिका थी। उनके पिता का नाम सोमभाई भील था तथा मां का नाम नवली बाई था। वे किसान थे। जिनका खेत रास्तापाल गांव के समीप ही था। वे खेती से ही अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे।

कालीबाई के पिता सोमभाई गोविंदगुरू के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। आदिवासियों में फैली हुई सामाजिक कुरीतियों को मिटाने एवं उनमें जाग्रति लाने के लिए गोविंदगुरू द्वारा बनाई हुई 'सम्प सभा' से प्रभावित होकर उन्होंने कालीबाई को पाठशाला भेजना शुरू किया था। कालीबाई भी पाठशाला से लौटकर अपने माता-पिता के घर और खेती के कार्यों में हाथ बंटाती थी।

आजादी से पूर्व ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ देशभर में आदिवासियों ने ही सैकड़ों युद्ध लड़े थे। वहीं ब्रिटिश गुलामी को नकारते हुए उनको नाकों चने चबवाये थे। इसी कारण देशभर के आदिवासियों पर अपराधी जनजाति अधिनियम लगाकर समकालीन रजवाड़ों और अंग्रेजों का भारत में क्रूरता और अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजे-रजवाड़े अपने क्षेत्र की ही जनता का बुरी तरह से दमन किया करते थे। 17 नवम्बर, 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर भील-मीणा आदिवासियों का नरसंहार किया गया था। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार लगभग 1500 से अधिक आदिवासियों को मौत के घाट उतारा था। सैकड़ों लहलुहान होकर कुछ समय बाद वे भी काल के ग्रास बन गए।

राजस्थान की रियासत डूंगरपुर के महारावल चाहते थे कि उनके राज्य में शिक्षा का प्रसार ना हो। क्योंकि शिक्षित होकर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाता है। उस समय अनेक शिक्षक अपनी जान पर खेलकर विद्यालय चलाते थे।

नानभाई खांट और सेंगाभाई जो रास्तापाल गांव में पाठशाला चला रहे थे। विद्यालय के लिए नानभाई खांट ने अपना भवन दिया था। इससे महारावल नाराज रहते थे। उन्होंने कई बार अपने सैनिक भेजकर नानभाई और सेंगाभाई रोट को विद्यालय बंद करने के लिए कहा, पर स्वतंत्रता और शिक्षा के प्रेमी यह दोनों महापुरुष अपने विचारों पर दृढ़ रहे। यह घटना 17 जून 1947 की है। डूंगरपुर का एक पुलिस अधिकारी कुछ जवानों के साथ रास्तापाल गांव पहुंचा। उसने नानभाई खांट और सेंगाभाई रोट को पाठशाला तुरंत बंद करने की चेतावनी दी। जब वह नहीं माने तो पुलिस ने बेत और बंदूक की बट से सेंगाभाई और नानभाई को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। दोनों मार खाते रहे और घायल हो गये, लेकिन विद्यालय बंद करने पर राजी नहीं हुए।[10,11,12]

नानभाई का वृद्ध शरीर इतनी क्रूर मार सह नहीं सका और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इतने पर भी पुलिस अधिकारी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने सेंगाभाई को अपने ट्रक के पीछे रस्सी से बांध दिया। उस समय वहां गांव के अनेक लोग उपस्थित थे। डर के मारे किसी को बोलने का साहस नहीं हो रहा था। उसी समय एक 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई वहां पहुंची। वह बालिका उसी विद्यालय में पढ़ती थी। इस समय वह जंगल में अपने पशुओं के लिए घास काट कर ला रही थी। उसके हाथ में तेज धार वाला हंसिया चमक रहा था।

उसने जब नानभाई और सेंगाभाई को इस दशा में देखा तो वह चिंतित होकर वहीं पर रुक गई। उसने पुलिस अधिकारी से पूछा कि इन दोनों को किस कारण पकड़ा गया है। पुलिस अधिकारी पहले तो चुप रहा, पर जब कालीबाई ने बार-बार पूछा तो उसने बता दिया कि महारावल के आदेश के विरुद्ध विद्यालय चलाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कालीबाई ने कहा कि विद्यालय चलाना अपराध नहीं है, शिक्षा ही हमारे विकास की कुंजी है।

आदिवासी समाज में शिक्षा की रोशनी लाने के लिए प्रजामंडल आंदोलन के आह्वान पर हर गांव में विद्यालय खोले जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी उसे इस प्रकार बोलते हुए देखकर बौखला गया। उसने कहा कि विद्यालय चलाने वाले को गोली मार दी जाएगी। कालीबाई ने कहा तो सबसे पहले मुझे गोली मारो, इस वार्तालाप में गांव वाले भी उत्साहित होकर महारावल लक्ष्मणसिंह के विरुद्ध नारे लगाने लगे। अंग्रेज अधिकारी के आदेश से ट्रक से बांधकर सेंगाभाई को बुरी तरह घायल अवस्था में घसीटने लगे। यह देखकर कालीबाई आवेश में आई और उसने हंसिए के एक ही वार से रस्सी काट दी।

पुलिस अधिकारी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और कालीबाई पर गोली चला दी। कालीबाई के सीने पर गोली लगने से लहलुहान होकर गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। इस लोमहर्षक घटना से सभी गांव वाले आक्रोशित हो गए।[11,12,13]

निष्कर्ष

आदिवासियों ने मारू ढोल बजा दिया और जिसके पास जो हथियार था वो लेकर पुलिस की तरफ पथराव शुरू कर दिया। मारू ढोल बजाना युद्ध का संकेत था। जिससे डरकर पुलिस वाले भाग गए। आदिवासियों ने सेंगाभाई रोट और कालीबाई को चिकित्सालय पहुंचाया। नानभाई खांट की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। उनका अन्तिम क्रियाकर्म रास्तापाल गांव में किया गया। दो दिन के बाद 20 जून, 1947 को कालीबाई भी शिक्षा की अलख को जगाकर शहीद हो गयी। इस प्रकार कालीबाई के अमर बलिदान से शिक्षक सेंगाभाई रोट के प्राण बच गए।[13]

उसके बाद पुलिस वालों का उस क्षेत्र में कभी आने का साहस नहीं हुआ। कुछ ही दिन बाद देश स्वतंत्र हो गया। आज डूंगरपुर और संपूर्ण राजस्थान में शिक्षा की ज्योति जल रही है। उसमें कालीबाई और नाना भाई जैसे बलिदानियों का योगदान अविस्मरणीय हैं। उस वीर बलिदानी बाल ज्वाला को आदिवासी समाज बारंबार जोहार के साथ नमन करता है और उसकी यश गाथा को सदा-सदा के लिए अनंतकाल तक अमर रखने का संकल्प दोहराता है।[14]

संदर्भ

1. PTI (1 September 2019). "Kalraj Mishra is new governor of Rajasthan, Arif Mohd Khan gets Kerala | India News - Times of India". The Times of India (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 1 September 2019.
2. ↑ "Rajasthan Profile" (PDF). Census of India. मूल से 16 September 2016 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 21 July 2016.

3. ↑ "MOSPI Net State Domestic Product, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India". अभिगमन तिथि 7 April 2020.
4. ↑ "Report of the Commissioner for linguistic minorities: 52nd report (July 2014 to June 2015)" (PDF). Commissioner for Linguistic Minorities, Ministry of Minority Affairs, Government of India. पृष्ठ 34–35. मूल (PDF) से 28 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 फ़रवरी 2016.
5. ↑ "Sub-national HDI – Area Database – Global Data Lab". hdi.globaldatalab.org (अंग्रेज़ी में). मूल से 23 September 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 September 2018.
6. ↑ "Census 2011 (Final Data) – Demographic details, Literate Population (Total, Rural & Urban)" (PDF). planningcommission.gov.in. Planning Commission, Government of India. मूल से 27 January 2018 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 3 October 2018.
7. ↑ सक्सेना, हरमोहन (2014). राजस्थान अध्ययन. जयपुर: राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर. पृष्ठ 3.
8. ↑ Jat, Madan; Jat (2018). Madan. Jat.
9. ↑ Kohli, Anju; Shah, Farida; Chowdhary, A. P. (1997). Sustainable Development in Tribal and Backward Areas (अंग्रेज़ी में). Indus Publishing. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7387-072-9.
10. ↑ गोपीनाथ शर्मा / 'Social Life in Medieval Rajasthan' / पृष्ठ ३
11. ↑ शर्मा, गोपीनाथ (1971). राजस्थान का इतिहास. आगरा: शिवलाल अग्रवाल एंड कम्पनी. पृष्ठ 7.
12. ↑ <http://hindi.mapsofindia.com/rajasthan/jaipur/places-of-interest/> Archived 2016-09-19 at the वेबैक मशीन जयपुर के दर्शनीय स्थल
13. ↑ [1]बेरोजगार सेवा केन्द्र सीकर
14. ↑ "राजस्थान जनरल नॉलेज". akresult.com.

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975

Impact Factor: 7.394